नमस्ते एक्सप्रेस

PRGI No. - GJHIN/26/A3565

प्रातःकालीन दैनिक

वर्षः01 | अंकः 153 | अहमदाबाद, शुक्रवार 20 नवम्बर, 2026 | मूल्यः 1.00 रुपये | पृष्ठः 6 | Email - namasteexpress2013@gmail.com | प्रबंध संपादकः आस्था पराते



पीएफ से 90% तक रकम निकाल सकेंगे

पहले 75% लिमिट थी-बेरोजगारी-बीमारी और बच्चों की पढ़ाई के लिए विड्रॉल कर सकेंगे



नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोग अब पीएफ से ज्यादा पैसा निकाल सकेंगे। EPFO ने 55 साल से कम उम्र के कर्मचारियों के लिए नौकरी के दौरान विड्रॉल की लिमिट 75% से बढ़ाकर 90% कर दी है। इसके अलावा, पीएफ से पैसा निकालने के लिए अब 1 साल तक नौकरी करने की शर्त नहीं रहेगी। नए नियम के तहत अब PF मेंबर बनने के सिर्फ 2 महीने बाद ही आप बेरोजगारी की स्थिति में पैसा निकाल पाएंगे।

केरल हाईकोर्ट बोला- बच्चे को गोद लिया हुआ कहना गलत

सरकारी कागजों में सिर्फ बेटा-बेटी लिखें, वे भी माता-पिता के अपने बच्चे, समान दर्जा मिले



तिरुवनंतपुरम। केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वारिस प्रमाणपत्र में किसी बच्चे के नाम के आगे गोद लिया हुआ बेटा या गोद ली हुई बेटी न लिखा जाए। सरकारी दस्तावेजों में उसे सिर्फ बेटा या बेटी ही लिखा जाए। कोर्ट ने कहा कि गोद लेने के बाद बच्चा कानूनी रूप से माता-पिता की संतान बन जाता है। ऐसे में उसे दूसरे बच्चों से अलग पहचान देने की जरूरत नहीं है। सभी बच्चों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन की बेंच ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। कोर्ट ने हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12 का भी जिक्र किया। याचिकाकर्ता महिला को 30 जून 1990 को गोद लिया गया था। उसके माता-पिता ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। सभी सरकारी दस्तावेजों में भी उसे बेटी ही लिखा गया था। जनवरी 2023 में मां की मौत के बाद बने वारिस प्रमाणपत्र में महिला को बेटी बताया गया। लेकिन अक्टूबर 2024 में पिता की मौत के बाद बने प्रमाणपत्र में उसके नाम के आगे गोद ली हुई बेटी लिख दिया गया। महिला ने इस अंतर पर आपत्ति जताई। उसने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रमाणपत्र से गोद ली हुई बेटी शब्द हटाने की मांग की।

रिपोर्ट- इस्लाम 2035 तक दुनिया का सबसे बड़ा धर्म होगा

भारत में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटेगी, अमेरिका में दोगुनी हो जाएगी



नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर धार्मिक आबादी में हो रहे बदलावों को लेकर अमेरिका की प्यू रिसर्च सेंटर की नई रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक, दुनिया की आबादी 2050 तक 9.30 अरब पहुंच सकती है, जो 2010 में करीब 6.90 अरब थी। रिपोर्ट के मुताबिक, 2010 के मुकाबले 2050 तक मुस्लिम आबादी करीब 73% बढ़ सकती है। यानी मुसलमानों की आबादी 1.6 अरब से बढ़कर लगभग 2.76 अरब हो जाएगी। 2020 से 2050 के बीच भारत में हिंदुओं की आबादी 17.6 करोड़ बढ़ने का अनुमान है। हालांकि, देश की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी घटने का अनुमान है। इसके बावजूद 2070 तक हिंदू भारत की कुल आबादी के तीन-चौथाई से ज्यादा बने रहेंगे। इस दौरान अमेरिका में हिंदुओं की आबादी दोगुनी हो जाएगी।

किसानों-कारोबारियों को गाली देने से देश नहीं बढ़ताः मोदी

हमने 12 साल में इकोनॉमी बदली, राहुल ने कहा था- भारत आर्थिक संकट की ओर



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि किसानों और कारोबारियों को गाली देने से देश आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में भारत की इकोनॉमी बदली है और 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पीएम का यह बयान राहुल गांधी के आरोपों के एक दिन बाद आया है। राहुल ने बुधवार को न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कहा था कि भारत आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। इसके पीछे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी खामियां हैं।

50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले

पीएम ने कहा कि 1970 के दशक में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तब भारत की आबादी करीब 50 करोड़ थी। लेकिन अर्थव्यवस्था पिछले 12-13 साल में बदली है। आज 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं।

भारतीय ग्राहकों को भी मिले एक्सपोर्ट जैसी क्वालिटी

पीएम ने कहा कि कुछ कंपनियां विदेशों के लिए बेहतर और भारत के लिए कम गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाती हैं। इस सोच को बदलना होगा। भारतीय ग्राहक भी अच्छी गुणवत्ता वाले सामान के हकदार हैं।

फिक्की देश का बड़ा उद्योग और व्यापार संगठन

फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारत के बड़े उद्योग और व्यापार संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। यह संगठन देश की कंपनियों, कारोबारियों और उद्योगों के हितों की बात सरकार के सामने रखता है। फिक्की सरकार को व्यापार, उद्योग, रोजगार और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सुझाव भी देता है। इसका मकसद देश में कारोबार और उद्योगों को बढ़ावा देना, निवेश के नए मौके बनाना और आर्थिक विकास में मदद करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गुरुवार को फिक्की का वार्षिक सम्मेलन और वार्षिक आम बैठक आयोजित हुई। इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और कारोबारियों व उद्योग जगत के लोगों को संबोधित किया।

ग्लोबल मार्केट के अवसरों का फायदा उठाएं

प्रधानमंत्री ने कारोबारियों से घरेलू बाजार तक सीमित न रहने की अपील की।
उन्होंने कहा कि कंपनियों को दूसरे देशों की जरूरतों और ग्राहकों की पसंद समझकर उत्पाद तैयार करने चाहिए।

सरकार कारोबारियों के सुझावों पर करेगी काम

मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म एक्सप्रेस के जरिए लगातार सुधार कर रही है। उन्होंने कारोबारियों से बिना झिझक अपनी समस्याएं और सुधारों से जुड़े सुझाव देने को कहा। सरकार उनके साथ खड़ी है।

रिसर्च और इनोवेशन पर दें ध्यान

पीएम ने कहा कि कंपनियों को ऐसे उत्पाद बनाने चाहिए, जो ग्राहकों की जरूरतों के मुताबिक हों और इस्तेमाल में आसान हों। इसके लिए बेहतर रिसर्च और नई तकनीक अपनाना जरूरी है।

अगले 10 साल में देश के लिए क्या करेंगे, यह सोचें

प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्य को सिर्फ नारा नहीं, बल्कि संकल्प बताया। उन्होंने कहा कि हमें 100 साल का इंतजार करने के बजाय यह सोचना चाहिए कि अगले 10 साल में देश के विकास के लिए क्या योगदान दे सकते हैं।

राहुल अमेरिका में बोले- 2024 का लोकसभा चुनाव अवैध था

लेकिन चुनाव का बायकॉट नहीं करेंगे; BJP बोली- राहुल का एआई मॉडल विदेश भेजे कांग्रेस



न्यूयॉर्क/नई दिल्ली। राहुल गांधी ने गुरुवार को अमेरिका में दावा किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव वैध नहीं था। उन्होंने कहा कि चुनाव में कई फर्जी मतदाता थे। एक ब्राजीलियाई महिला के नाम से विधानसभा चुनाव में 23 बार वोट डाले गए, जबकि वह कभी भारत आई ही नहीं। शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रॉबर्ट पेप के साथ बातचीत में राहुल से पूछा गया कि चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों के बावजूद विपक्ष चुनावों का बायकॉट क्यों नहीं करताड इस पर उन्होंने कहा- चुनाव का बहिष्कार करने से भारतीय लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती। राहुल के बयानों पर BJP ने निशाना साधा। BJP प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को राहुल को विदेश भेजने पर पैसा खर्च करने के बजाय उनका AI मॉडल भेजना चाहिए। राहुल बार-बार एक ही बातें दोहराते हैं, AI मॉडल उनसे बेहतर काम कर सकता है।

राहुल की बातचीत की 4 बड़ी बातें, कहा- लोग बिना डरे अपनी बात रखें

1. चुनावी बहिष्कार का कदम नहीं उठा रहेः हम जानबूझकर चुनावी बहिष्कार का कदम नहीं उठा रहे हैं और हमें भरोसा है। चुनाव आयोग खुद अब अंदर से हमें जानकारी दे रहा है। इसलिए यह ढांचा कब ढहेगा, यह सिर्फ समय की बात है। चुनाव आयोग में वरिष्ठ लोग अब कह रहे हैं कि हम यह और नहीं कर सकते।

2. गैर-लोकतांत्रिक भारत स्वीकार नहींः हम गैर-लोकतांत्रिक भारत स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। यह भारत के अधिकांश लोगों की भावना है।

3. लोग बिना डरे अपनी बात कह सकें: विपक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि लोगों की बिना डर अपनी बात कहने की सबसे बड़ी ताकत फिर से बहाल हो। यह ताकत आगे भी भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनी रहेगी। हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हम यह लड़ाई जीत रहे हैं।

4. 2024 के चुनाव की वैधता पर सवालः 2024 के लोकसभा चुनाव भी वैध नहीं थे। 2024 के चुनाव में मतदाता अवैध थे। कई फर्जी मतदाता थे। ऐसे में चुनाव वैध कैसे हो सकते हैं। मैं फिर बताऊंगा कि एक ब्राजीलियाई महिला, जो कभी भारत नहीं आई, उसने भारत में एक विधानसभा चुनाव में 23 बार मतदान किया।

राहुल बोले- अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो समय कम है

जलवायु संकट से निपटने के लिए भारत के पास कितना समय है सवाल पर राहुल ने मजाकिया लहजे में कहा कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपके पास समय नहीं है। मैं अपने घर में एयर प्यूरीफायर (हवा साफ करने वाली मशीनें) लगवा रहा हूं, क्योंकि मुझे दिनभर सिरदर्द रहता है। दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण की वजह से जितने लोग परेशानियां झेल रहे हैं, वह बेहद चिंताजनक है। छोटे-छोटे बच्चों को फेफड़ों की बीमारियां हो रही हैं। लोग कैंसर जैसी बीमारियों से मर रहे हैं।
इजराइल से भारत के संबंधों से जुड़े सवाल पर कहा कि अक्टूबर में इजरायल में जो कुछ हुआ, मैं उसकी निंदा करता हूं। मुझे लगता है कि वह बेहद भयावह था। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था।

सुप्रीम कोर्ट बोला- भारत अमीर देश, लेकिन स्वच्छता में खराब

वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा न हो तो देश की इमेज खराब होती है



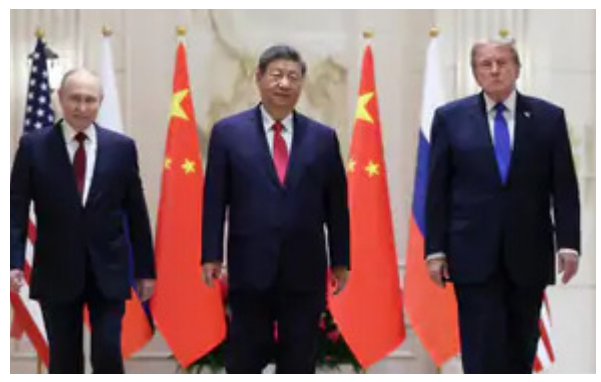
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भारत अमीर देश है, लेकिन स्वच्छता के मामले में हमारा प्रदर्शन खराब है। खराब स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन का असर समाज और देश की इमेज पर पड़ता है। कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू नहीं होने पर चिंता जताई। जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने नगर निगमों की पर्यावरण नियमों के पालन से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू करने की निगरानी के लिए शुरुआती दो चरण पूरे हो चुके हैं। इनमें काम शुरू करना और निगरानी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टरों को अपने क्षेत्रों में बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान करने का निर्देश दिया। उन्हें यह काम स्थानीय निकायों के साथ मिलकर करना होगा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट की 4 प्रमुख बातें

संविधान में शक्तियों का बंटवारा उसकी मूल संरचना का हिस्सा है। संसद ने एन्वायर्नमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 बनाया है। कार्यपालिका ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 बनाए हैं। कानून और नियम मौजूद होने के बावजूद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 और 2026 का प्रदर्शन संसद के तय लक्ष्य से कम है। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के संवैधानिक अधिकार का संरक्षक है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के जरिए स्थानीय निकायों को लगातार निर्देश देने की जिम्मेदारी उठाई है।

ट्रम्प-जिनपिंग और पुतिन की पहली बार एक साथ मीटिंग

जिनपिंग बोले- परमाणु हथियार इंसान के सिर पर लटकती तलवार, इन्हें खत्म करें



शेनझेन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के शेनझेन शहर में ऐतिहासिक बैठक की। यह पहली बार हुआ जब तीनों नेताओं ने एक साथ त्रिपक्षीय बैठक की। मीटिंग में सबसे पहले परमाणु हथियारों के खतरों पर बातचीत हुई। जिनपिंग ने परमाणु हथियारों को इंसानियत के सिर पर लटकती तलवार बताया। उन्होंने कहा कि इन्हें पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। पुतिन ने कहा कि रूस, चीन और अमेरिका तीनों ने दूसरे विश्व युद्ध में जीत हासिल की थी। इसलिए दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी इन तीनों देशों की है। ट्रम्प ने कहा कि वे इस बात से बेहद खुश हैं कि तीनों देशों के बीच पहली बार त्रिपक्षीय बैठक हो रही है। यह इतिहास रचने जैसा है।

ट्रम्प, जिनपिंग और पुतिन के साझा बयान में 4 बड़े फैसले

रूस ने ट्रम्प, जिनपिंग और पुतिन की बैठक के बाद जारी साझा बयान का पूरा मसौदा जारी किया है। इसमें चार मुख्य बातें कही गई हैं।

संयुक्त राष्ट्र में सुधारः संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में सुधार करने पर सहमति बनी।

तेल की सप्लाई बढ़ानाः पेट्रोलियम का उत्पादन और सप्लाई बढ़ाने पर सहमति जताई गई।

सरकारी अधिकारियों को कानूनी छूटः किसी देश के सरकारी अधिकारियों को उनके आधिकारिक कामों के लिए दूसरे देशों की अदालतों में कानूनी कार्रवाई से छूट मिलनी चाहिए। साथ ही, ICC को अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

परमाणु युद्ध का खतरा कम करनाः परमाणु हथियारों से जुड़े खतरे कम करने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी। बयान में कहा गया कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही इसे कभी लड़ा जाना चाहिए।

ट्रम्प अमेरिका के लिए रवाना हुए

पुतिन और जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रम्प अमेरिका के लिए रवाना हुए। ट्रम्प अपनी इस यात्रा के दौरान लगभग 26 घंटे तक चीन के शेनझेन शहर में रहे।

पुतिन भी बैठक खत्म होने के बाद रवाना हुए

पुतिन भी त्रिपक्षीय बैठक खत्म होने के बाद किलिन विला से रवाना हो गए। वहां जिनपिंग उन्हें कार तक छोड़ने आए। बैठक के बाद तीनों नेताओं ने मीडिया से कोई बात नहीं की। इससे पहले ट्रम्प का काफिला भी बैठक वाली जगह से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका था। पुतिन ने कहा कि ट्रम्प के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक में यूक्रेन युद्ध सबसे अहम मुद्दा रहा। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले उन्होंने शी जिनपिंग के साथ भी यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा की थी। पुतिन का यह बयान अमेरिका, रूस और चीन के बीच त्रिपक्षीय बैठक की शुरुआत में आया।

विशेष एन आई लोक अदालत कल, राजीनामे से निपटेंगे विवाद

लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने और पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद निपटाने का मौका देने के लिए जिलेभर में विशेष एन आई लोक अदालत आयोजित होगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटपुतली के निर्देशन पर विशेष एन आई लोक अदालत का आयोजन शनिवार 21 नवंबर को किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटपुतली की सचिव नीलम मीणा (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) ने बताया कि लोक अदालत में, चेक अनादरण, बैंक ऋण के राजीनामा योग्य मामलों को शामिल किया गया है।

इंदिरा गांधी के आदर्शों और योगदान को किया याद

सिवाना (एम ताहिर)। सिवाना कस्बे के निकट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालियों का बेरा, भीमगोड़ा में गुरुवार को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य भावना सहित समस्त शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने इंदिरा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें



भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में राज्य पुरस्कृत व्याख्याता ओमप्रकाश कड़वासरा ने इंदिरा गांधी के जीवन चरित्र, राजनीतिक सफर एवं राष्ट्र निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति, साहसिक निर्णयों और नेतृत्व क्षमता के कारण आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा, गरीबी हटाओ का नारा तथा प्रिवी पर्स की समाप्ति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उनके नेतृत्व और ऐतिहासिक फैसलों ने देश की राजनीति एवं विकास की दिशा को प्रभावित किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को इंदिरा गांधी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित रहने का संदेश दिया गया।

सर्दी ने दी दस्तक, बदलने लगी सिवाना की दिनचर्या

पांच साल के मौसम आंकड़ों में जनवरी की ठंड का दिखा असर, रात होते ही गर्म कपड़ों में नजर आने लगे लोग

सिवाना (एम. ताहिर)। सिवाना उपखंड क्षेत्र में धीरे-धीरे सर्दी का असर बढ़ने लगा है। शाम ढलते ही मौसम में ठंडक घुलने और सर्द हवाओं का दौर शुरू होने से लोगों को ठंड का अहसास होने लगा है। दिन और रात के तापमान में बदलाव के चलते आमजन की दिनचर्या भी बदलने लगी है। खासकर देर रात और अलसुबह ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है। लोगों ने अब गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। मौसम में आ रहे बदलाव का असर अब घरों में भी दिखाई देने लगा है। गर्मी के दिनों में दिन-रात चलने वाले कूलर, पंखे और एसी का उपयोग धीरे-धीरे कम होने लगा है। वहीं बाजारों में भी ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ने की संभावना है। सुबह और शाम लोग गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं।

पिछले पांच वर्षों के आंकड़े भी बताते हैं सर्दी का मिजाज

सिवाना के उपलब्ध मौसम रिकॉर्ड पर नजर डालें तो वर्ष 2021 से 2025 के दौरान दर्ज वार्षिक न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री, 2022 में 7.4 डिग्री, 2023 में 4.5 डिग्री, 2024 में 7.4 डिग्री और 2025 में 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन आंकड़ों में वर्ष 2023 सबसे ठंडा रहा। वहीं मौसम संबंधी ऐतिहासिक औसत के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में नवंबर से रात के तापमान में गिरावट शुरू हो जाती है और जनवरी सबसे ठंडा महीना रहता है। ऐसे में आने वाले दिनों में सर्दी का असर और बढ़ने की संभावना के बीच लोगों को ठंड से बचाव के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है।

रात की ठंड से बचाव जरूरी

बदलते मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। चिकित्सकों की सलाह के अनुसार ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े पहनने और सुबह-शाम अनावश्यक ठंड के संपर्क में आने से बचना चाहिए।

सीलू गांव में 21 नवंबर से श्रीमद्भागवत कथा का भव्य शुभारंभ

गणपत दवे सांचौर/सीलू। धार्मिक आस्था, भक्ति एवं सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से सीलू गांव में 21 नवंबर को श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन को लेकर गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। कथा का वाचन परम पूज्य कथा वाचक प्रहलाद दास महाराज के श्रीमुख से किया जाएगा।

आयोजन के प्रथम दिन 21 नवंबर को गो समृद्धि भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा के माध्यम से धार्मिक महोत्सव का विधिवत आगाज होगा। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में मातृशक्ति, युवाओं, श्रद्धालुओं एवं धर्मप्रेमियों के शामिल होने की संभावना है। पारंपरिक वेशभूषा, धार्मिक जयकारों एवं भक्ति संगीत के साथ निकलने वाली कलश यात्रा गांव में आध्यात्मिक वातावरण का संचार करेगी।

21 नवंबर को होगा तुलसी विवाह का भव्य आयोजन

श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव के अंतर्गत 21 नवंबर को तुलसी विवाह का विशेष धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। तुलसी विवाह सनातन धर्म की महत्वपूर्ण धार्मिक परंपराओं में से एक है। इस अवसर पर विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तुलसी विवाह संपन्न करवाया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धालुओं को धार्मिक परंपराओं, संस्कारों एवं भक्ति भावना से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

कथा वाचन में होगा भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन



परम पूज्य प्रहलाद दास महाराज श्रीमद्भागवत कथा के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं, भक्त प्रह्लाद की अटूट भक्ति, धर्म एवं अधर्म के संघर्ष तथा जीवन में सदाचार, संस्कार और भक्ति के महत्व का विस्तार से वर्णन करेंगे। कथा श्रवण से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान एवं जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी।

आयोजन की तैयारियां पूरी, सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे

श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव को लेकर आयोजन समिति एवं ग्रामीणों द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। आयोजन को सफल एवं भव्य बनाने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से जुटे हुए हैं। कथा स्थल की सजावट, श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। ग्रामीणों एवं कार्यकर्ताओं में आयोजन को लेकर विशेष उत्साह है। सभी कार्यकर्ता आपसी सहयोग एवं समर्पण भावना के साथ व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, ताकि कथा महोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

धर्म, संस्कृति और गौसेवा का संदेश देगा महोत्सव

सीलू गांव में आयोजित होने जा रहा यह धार्मिक महोत्सव केवल कथा श्रवण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज में धार्मिक जागरूकता, आपसी भाईचारे, संस्कारों एवं गौमाता के प्रति सेवा और समर्पण की भावना को भी प्रोत्साहित करेगा। गो समृद्धि कलश यात्रा के आयोजन से गौ संरक्षण एवं भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता का संदेश भी प्रसारित होगा। ग्रामीणों एवं आयोजन से जुड़े कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयासों से सीलू गांव में 21 नवंबर से शुरू होने जा रहा श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव क्षेत्र के लिए एक भव्य धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजन बनने जा रहा है।

रेवदर में युवा विरासत महोत्सव के तहत स्कूलों में हुए विविध आयोजन

युवाओं ने कला, विचार और इतिहास से जुड़ी गतिविधियों में लिया भाग





रेवदर (शकूर खान रंगरेज)। राजस्थान युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार रेवदर ब्लॉक युवा कांग्रेस के तत्वावधान में 14 से 19 नवंबर तक युवा विरासत महोत्सव (Youth Heritage Festival) के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर आयोजित इस महोत्सव के माध्यम से युवाओं को कला, विचार, इतिहास, अभिव्यक्ति और संवाद से जोड़ने का प्रयास किया गया। ब्लॉक स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों के तहत विभिन्न विद्यालयों में पोस्टर विमोचन, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता एवं ओपन माइक जैसे आयोजन किए गए। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं श्रीमती इंदिरा गांधी के जीवन, व्यक्तित्व, विचारों और देश के प्रति उनके योगदान से परिचित कराने के उद्देश्य से जीवनी आधारित वीडियो प्रदर्शन एवं अन्य गतिविधियां आयोजित की गईं। महोत्सव के दौरान विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा, विचारों और रचनात्मकता को प्रस्तुत करने का अवसर मिला। निबंध एवं भाषण प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए, वहीं जीवनी आधारित कार्यक्रमों के जरिए देश के इतिहास और प्रमुख नेताओं के योगदान को जानने का अवसर मिला। इन सभी कार्यक्रमों का आयोजन ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष विनोद सिंह सोलंकी के नेतृत्व में किया गया। आयोजन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए कार्यक्रमों को सफल बनाने में सहयोग किया। इस मौके पर ईश्वर धरमाणी, शरीफ खान, पवन गर्ग, जयंती लखारा, राणा राम कोली, सुरेश कोली रानाडी, रवि लखारा, लक्ष्मण घांची, महेंद्र कुमार सहित दर्जनों युवा कांग्रेस के सदस्य मौजूद रहे।

करेली के युवा ने सोशल मीडिया पर गाड़े सफलता के झंडे, 1 लाख फॉलोअर्स के साथ अशोक दान चारण का डिजिटल जलवा

रेवदर (शकूर खान रंगरेज)। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी रचनात्मकता और हुनर के दम पर पहचान बनाने वाले युवाओं की सूची में रेवदर क्षेत्र के करेली गांव के अशोक दान चारण ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। अशोक ने अपने इंस्टाग्राम पेज 'EditingWalaBoyy' पर 1 लाख (100+) फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर गांव, रेवदर क्षेत्र, आबूरोड और सिरोही जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर मित्रों, शुभचिंतकों और ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए बधाइयां दी हैं।



सीमित संसाधनों से मेहनत के दम पर बनाई पहचान

अशोक दान चारण की सफलता उनके निरंतर प्रयास, रचनात्मक सोच और वीडियो एडिटिंग के हुनर का परिणाम है। करेली जैसे छोटे गांव से सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखने वाले अशोक ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने कौशल को निखारने और कंटेंट को बेहतर बनाने पर लगातार काम किया। धीरे-धीरे उनके वीडियो दर्शकों के बीच लोकप्रिय होने लगे और आज उन्होंने इंस्टाग्राम पर 1 लाख फॉलोअर्स का मुकाम हासिल कर लिया है।

राजस्थान में बढ़ रही लोकप्रियता

अशोक का इंस्टाग्राम पेज 'EditingWalaBoyy' युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है। रेवदर और आबूरोड क्षेत्र के साथ राजस्थान के अन्य इलाकों में भी उनके कंटेंट को पसंद किया जा रहा है। वीडियो एडिटिंग के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाने वाले अशोक की उपलब्धि ग्रामीण युवाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिभा दिखाने का एक प्रेरक उदाहरण बन रही है।

ग्रामीण युवाओं के लिए बने प्रेरणा

अशोक के 1 लाख फॉलोअर्स पूरे होने पर करेली गांव सहित आसपास के क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। ग्रामीणों और मित्रों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अशोक की उपलब्धि यह संदेश देती है कि प्रतिभा, मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास के जरिए गांव से निकलकर भी डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बनाई जा सकती है। उनकी इस सफलता से रेवदर उपखंड और सिरोही जिले के लोगों में गर्व का माहौल है।

फर्जी क्रिप्टो-करेंसी में निवेश के नाम पर 87लाख की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। साइबर पुलिस थाना जयपुर ने फर्जी क्रिप्टो करेंसी Flinty Coin में निवेश के नाम पर 87 लाख रुपए की साइबर ठगी का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 10 से 15 प्रतिशत मासिक मुनाफे का लालच देकर परिवादी से लाखों रुपए निवेश करवाए थे। इसके लिए Flinty.live नाम से फर्जी वेबसाइट और एप्लीकेशन तैयार की गई थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी शुरुआत में निवेशकों को मुनाफे के नाम पर कुछ रकम लौटाते थे, जिससे उनका भरोसा जीतकर बड़ी रकम निवेश करवाई जाती थी। स्पेशल पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान घनश्याम कांदेल (35) निवासी सामोद और मोहित कलोया (27) निवासी कालाडेरा, जयपुर ग्रामीण के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को सेंट्रल जेल जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ठगी के पैसे की रकम से करीब 1 करोड़ रुपए की एफडी करवाई थी। कुछ समय बाद ही एफडी को गिरवी रख लोन लिया था। इसके बाद मर्सडीज गाड़ी खरीद ली। हालांकि पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने ठगी के इरादे से Motion Mode&ys Pvt. Ltd. नाम से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऑनलाइन गेमिंग कंपनी का ऑफिस खोला था।

जयपुर में ढोल बजाकर तीन अधिकारियों की कुर्सी कुर्क

जयपुर। जयपुर के जल भवन स्थित PHED मुख्यालय में चीफ इंजीनियर सहित तीन अधिकारियों की कुर्सियां कुर्क की गई। ठेकेदार का भुगतान नहीं होने पर कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। गुरुवार दोपहर ढोल वाले के साथ वकील और अमीन पीएचईडी मुख्यालय पहुंचे। ढोल बजाकर चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक कुमार चौरड़िया और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर (मटेरियल मैनेजमेंट-IV) अरुण कुमार जांगिड़ के ऑफिस के गेट पर नोटिस चस्पा किया। कार्रवाई के दौरान सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अशोक कुमार चौरड़िया ऑफिस में ही मौजूद थे। इसके बाद चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी भी मौके पर पहुंचे थे। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर आज लीव पर थे। एडवोकेट राजू अंबेडकर ने बताया- मेरे क्लाइंट सचदेवा मेटल्स जालंधर की कंपनी है। कंपनी ने साल 2018, 2019 और 2020 में PHED को मटेरियल सप्लाई किया था। कंपनी को नियमानुसार 45 दिन में भुगतान करना था, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। अब ब्याज सहित बकाया रकम 25 लाख रुपए से ज्यादा है। इसके बाद कंपनी ने MSME काउंसिल में क्लेम किया। काउंसिल ने हमारे पक्ष में आदेश जारी किया। इसके बाद भी भुगतान नहीं होने पर कोर्ट में वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की गई। कोर्ट ने आदेश में संबंधित कुर्सियों को बेचने, दूसरी जगह ले जाने या किसी अन्य को देने पर रोक लगाई है।

45 दिन में भुगतान नहीं तो MSME काउंसिल में कर सकते क्लेम

एडवोकेट राजू अंबेडकर ने बताया- यदि कोई सप्लायर **MSME** के दायरे में आता है। विभाग या कंपनी उसका भुगतान 45 दिन में नहीं करती है तो वह **MSME** काउंसिल में क्लेम कर सकता है। काउंसिल मामले की सुनवाई के बाद भुगतान के लिए आदेश जारी करती है। इसमें नियमों के अनुसार ब्याज भी देना होता है। उन्होंने बताया- इस मामले में भी काउंसिल ने हमारे क्लाइंट के पक्ष में आदेश दिया था, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। ऐसे में कोर्ट में कार्रवाई के लिए आवेदन किया था। उन्होंने बताया- **MSME** के मामलों में **RBI** के नियमों के अनुसार निर्धारित ब्याज दर से तीन गुना ब्याज देना होता है।

खारा-सांचौर में श्री जानकी गो नवरात्रि महा महोत्सव का भव्य समापन

भगवान श्रीकृष्ण को लगाया छप्पन भोग, गोमाता के लिए भी हुआ विशेष आयोजन



गणपत दवे सांचौर। खारा-सांचौरश्री कृष्ण गोशाला समिति खारा-सांचौर के तत्वावधान में आयोजित श्री जानकी गो नवरात्रि महामहोत्सव का धार्मिक उल्लास, वैदिक मंत्रोच्चार एवं भक्तिमय वातावरण के बीच भव्य समापन हुआ। महोत्सव के समापन अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण की विशेष पूजा-अर्चना, छप्पन भोग एवं गोमाता की आराधना सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। वहीं, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति कर महोत्सव का विधिवत समापन किया गया। महोत्सव के दौरान क्षेत्र में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिकता का विशेष माहौल देखने को मिला। प्रतिदिन श्रद्धालुओं ने धार्मिक आयोजनों में भाग लेकर धर्मलाभ प्राप्त किया। भागवत कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं, धर्म, भक्ति, सदाचार, संस्कार एवं मानव जीवन में सेवा और परोपकार के महत्व का संदेश दिया गया।

श्रद्धेय प्रहलाद दास महाराज ने किया भागवत कथा का वाचन

महोत्सव में भागवत कथा का वाचन श्रद्धेय प्रहलाद दास महाराज ने अपनी अमृतमयी वाणी से किया। महाराज ने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं एवं महिमा का वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को धर्म के मार्ग पर चलने, गोसेवा करने, जरूरतमंदों की सहायता करने तथा जीवन में सदैव सेवा और समर्पण की भावना बनाए रखने का संदेश दिया। कथा श्रवण के दौरान श्रद्धालु भक्तिरस में सराबोर नजर आए।

भगवान श्रीकृष्ण को विधि-विधान से लगाया छप्पन भोग

महोत्सव के समापन अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण को वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि-विधान के साथ छप्पन भोग अर्पित किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान के यजमान भूराराम चौधरी रहे। भगवान श्रीकृष्ण को विभिन्न प्रकार के पकवानों एवं व्यंजनों का भोग लगाकर क्षेत्र में सुख-समृद्धि, खुशहाली एवं मंगलमय जीवन की कामना की गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।

गोमाता के लिए भी लगाया गया छप्पन भोग, गोसेवा का दिया संदेश

महोत्सव का विशेष आकर्षण गोमाता के प्रति श्रद्धा, आस्था एवं समर्पण का भाव रहा। भगवान श्रीकृष्ण को छप्पन भोग अर्पित करने के साथ ही गोमाता के लिए भी विशेष रूप से छप्पन भोग लगाया गया।



गोमाता की पूजा-अर्चना कर उनके प्रति सम्मान एवं सेवा भावना प्रकट की गई। आयोजन के माध्यम से समाज को गोवंश की सेवा, सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आगे आने का संदेश दिया गया। भगवान श्रीकृष्ण का गोमाता के साथ विशेष संबंध रहा है। ऐसे में इस धार्मिक महोत्सव में गोआराधना एवं गोसेवा को विशेष महत्व प्रदान किया गया।

यजमान भूराराम चौधरी ने जताया गोसेवा के प्रति संकल्प

कार्यक्रम के यजमान भूराराम चौधरी ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि वे गोमाता की सेवा के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पथमेड़ा महाराज जी के आशीर्वाद से वे निरंतर गोसेवा के कार्यों में लगे रहेंगे तथा गोमाता की सेवा, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सदैव समर्पित रहेंगे। उन्होंने कहा कि गोमाता की सेवा करना सौभाग्य और पुण्य का कार्य है। गोसेवा के माध्यम से समाज में धर्म, करुणा, दया एवं मानवता की भावना को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने आगे भी पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ गोसेवा के कार्यों में अपना योगदान देते रहने का संकल्प व्यक्त किया।

वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति

महोत्सव के अंतिम दिन विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न हुई। यज्ञ में आहुतियां अर्पित कर विश्व शांति, जनकल्याण, क्षेत्र की खुशहाली, अच्छी वर्षा, सुख-समृद्धि एवं गोवंश के संरक्षण की मंगलकामना की गई। पूर्णाहुति के दौरान श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेकर पुण्यलाभ प्राप्त किया।

धर्म, भक्ति और गोसेवा का दिया प्रेरणादायक संदेश

श्री कृष्ण गोशाला समिति खारा-सांचौर के तत्वावधान में आयोजित इस महामहोत्सव ने धार्मिक आस्था के साथ समाज में गोसेवा, संस्कार, सेवा और समर्पण की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया। भागवत कथा के आध्यात्मिक विचारों, भगवान श्रीकृष्ण के छप्पन भोग, गोमाता की विशेष आराधना एवं यज्ञ की पूर्णाहुति ने आयोजन को विशेष धार्मिक महत्व प्रदान किया। इस प्रकार श्री जानकी गो नवरात्रि महामहोत्सव का समापन श्रद्धा, भक्ति एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ। आयोजन ने एक के साथ गोमाता की सेवा और संरक्षण भी समाज का महत्वपूर्ण दायित्व है।

आवश्यकता है





अहमदाबाद से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र को गुजरात के सभी जिलों में संवाददाता तथा विज्ञापन प्रतिनिधि की आवश्यकता है। अपना बायोडाटा मेल करें:



namasteexpress2013@gmail.com

संपर्क:

92512 77111 / 74900 50044

चिंतन

अंतरविरोधों के बीच कैसे बनेगी सहमति



कॉप-31

प्रमोद भार्गव

वैश्विक राजनीति में तीन महाशक्तियों के शीर्ष नेताओं का एक मंच पर आना अपने आप में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या गहरे मतभेदों और परस्पर विरोधी हितों के बीच कोई सहमति बन पाएगी? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चीन के शेनझेन में होने वाली त्रिपक्षीय बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। तीनों नेता एपेक समिट के स्वागत डिनर में एक साथ नजर आए। यह तस्वीर कूटनीतिक लिहाज से भले ही आकर्षक हो, लेकिन इसके पीछे मौजूद अंतरविरोधों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान युद्ध, परमाणु हथियारों का खतरा, वैश्विक व्यापार, टैरिफ, तेल और सामरिक वर्चस्व जैसे मुद्दों पर तीनों देशों के हित एक-दूसरे से टकराते रहे हैं। ऐसे में बैठक की सफलता केवल आपसी गर्मजोशी से नहीं, बल्कि ठोस सहमति बनाने की क्षमता से तय होगी। इस मुलाकात के कूटनीतिक महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रोटोकॉल तोड़कर ट्रम्प का स्वागत करने खुद एयरपोर्ट पहुंचे। जिनपिंग का यह कदम महज औपचारिकता नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ रिश्तों को महत्व देने का राजनीतिक संदेश भी है। इससे पहले सितंबर में अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रम्प भी जिनपिंग के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। यानी दोनों देश कूटनीतिक शिष्टाचार के जरिए रिश्तों में गर्मजोशी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, तकनीक पर नियंत्रण, ताइवान और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव को लेकर गहरे मतभेद हैं। दूसरी ओर, रूस और अमेरिका के संबंध यूक्रेन युद्ध और प्रतिबंधों के कारण तनावपूर्ण रहे हैं। चीन और रूस की नजदीकी भी अमेरिकी रणनीतिक चिंताओं का विषय है। ऐसे में तीनों देशों के लिए एक साझा एजेंडे पर सहमत होना आसान नहीं होगा। ईरान युद्ध और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका ने इन चुनौतियों को और गंभीर बना दिया है। यदि दुनिया की तीन बड़ी ताकतें इन मुद्दों पर जिम्मेदार भूमिका निभाती हैं तो तनाव कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। इस बैठक के लिए शेनझेन का चयन भी प्रतीकात्मक महत्व रखता है। कभी मछुआरों का छोटा-सा गांव रहा यह शहर चीन के आर्थिक और तकनीकी सामर्थ्य का बड़ा केंद्र बन चुका है। जिनपिंग ने भी शेनझेन को चीन के पांच दशक के विकास का प्रतीक बताते हुए दुनिया को यहां आने का संदेश दिया। तीनों देशों के बीच सहमति बनने का असर केवल उनके आपसी संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, निवेश और सुरक्षा व्यवस्था भी इससे प्रभावित होगी। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए भी इन समीकरणों का विशेष महत्व है। दुनिया पहले ही युद्धों, आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव से जूझ रही है। ऐसे में महाशक्तियों के बीच टकराव का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। बहरहाल, कूटनीति में मुलाकातें संभावनाओं के दरवाजे खोलती हैं, लेकिन समाधान की गारंटी नहीं होती। ट्रम्प, पुतिन और जिनपिंग को समझना होगा कि शक्ति प्रदर्शन और एक-दूसरे को दबाने की रणनीति से स्थायी शांति संभव नहीं है। हाथ मिलाने और साथ बैठकर भोजन करने की तस्वीरें तभी सार्थक होंगी, जब बातचीत मतभेद कम करने और साझा समाधान तलाशने तक पहुंचेगी। असली चुनौती यही है कि अंतरविरोधों के बीच सहमति का रास्ता कैसे निकले।

वादे पूरे होने पर थमेगी तापमान में वृद्धि

दुनिया की निगाहें तुर्किये के अंताल्या नगर में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, यानी कॉप-31 पर टिकी हैं। इसका मुख्य लक्ष्य पुराने जलवायु सम्मेलन के वादों को धरातल पर उतारना है। भारत जलवायु न्याय और विकासशील देशों के लिए वित्तीय मदद की पुरजोर पैरवी कर रहा है। करीब 200 देशों के इस सम्मेलन में अमेरिका आधिकारिक रूप से अनुपस्थित है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने लगातार दूसरी बार इस सम्मेलन में कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा है। पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के हटने के बाद से व्हाइट हाउस ने इन वार्ताओं से दूरी बना ली है, जिससे वह विकासशील देशों को किसी भी प्रकार की आर्थिक एवं तकनीकी मदद से बचा रहे। ऐसे में यहां बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ग्रीनहाउस दुष्प्रभावों से लड़ने के लिए धन कहां से मिलेगा? हालांकि तुर्की मेजबान और अध्यक्षता के रूप में कार्य योजना का दायित्व संभाल रहा है और ऑस्ट्रेलिया वार्ता के साथ समझौते का प्रारूप तैयार करेगा। विकासशील देशों के लिए 2035 तक सालाना 300 अरब डॉलर जलवायु वित्त जुटाने का लक्ष्य रखा है। पेरिस समझौते से अमेरिका के हटने के बाद पैदा हुए आर्थिक अंतर की पूर्ति के लिए अन्य विकसित देशों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। इस बार मुख्य एजेंडे में स्वच्छ ऊर्जा और विद्युतिकरण के जरिए वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेलिस्यस तक लाना है। इस हेतु जीवाष्म ईंधन (कोयला, तेल और गैस) पर निर्भरता घटाने और परिवहन व उद्योगों में विद्युतिकरण बढ़ाने पर सहमति बनाई जा रही है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव बातचीत में प्रयास कर रहे हैं कि आर्थिक एवं तकनीकी रूप में समृद्ध संपन्न पश्चिमी यूरोप सम्मेलन में हुए वादों को पूरा करने की संयुक्त जिम्मेदारी उठाए। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा की सस्ती एवं प्रभावी तकनीकें विकासशील देशों को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की शर्तों का पालन किए बिना मुफ्त में दे। इस ऊर्जा के भंडारण के उपायों से जुड़ी तकनीकें भी दें। जलवायु लक्ष्यों को साधना है तो ऐसा जरूरी है, क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश ने सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता 164 गीगावाट करके बड़ी छलांग तो लगाई है, लेकिन भंडारण तकनीक के अभाव में 17-18 प्रतिषत ऊर्जा ही उपयोग में आ रही है।



ऐसे में भारत को कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन भी बड़ी मात्रा में करना पड़ रहा है। साफ है, अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए भारत जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा उत्पादन को पूरी तरह बंद नहीं कर सकता है।

अतएव भारत जैसे देशों को धन और प्रौद्योगिकी दोनों की जरूरत है? वैसे भी इस सम्मेलन में भारत और जर्मनी के पास 2035 तक स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सम्मेलन में भागीदार देशों के बीच आम सहमति बनाए जाने की जिम्मेदारी है, जिससे तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक लाया जा सके। नवीनतम तकनीक से दक्ष निगरानी संचार उपग्रह ही मौसम के पूर्वानुमान, लगाकर प्राकृतिक आपदा किस भू-क्षेत्र में संभावित है, इसकी सूचना एवं भयावहता की चेतावनी दे सकते हैं। कृत्रिम बुद्धि आधारित ये संचार सूचनाएं यदि आपदा पूर्व मिल जाती हैं तो अत्यधिक बारिश, समुद्री चक्रवात, सौर तूफान और भू-गर्भीय हलचलों के परिणाम से निकले विस्फोटक भूकंपों से न केवल मानव आबादी बची रहेगी, बल्कि मानवों को सुरक्षित रखने वाले संसाधन भी सुरक्षित रहेंगे। अतएव कार्बन को अवशोषित, ग्रीन हाइड्रोजन, उन्नत इलेक्ट्रिक बैटरी और स्वच्छ ऊर्जा हासिल करने की दक्षता से जुड़ी तकनीकें विकासशील देशों को निशुल्क देने की सुविधा पर आम सहमति बनती है तो दूषित कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर पृथ्वी के बढ़ते तापमान को 1.5 डिग्री पर लाने के लक्ष्य को साधने की उम्मीद बढ़ जाएगी? जीवाश्म ईंधन के परिप्रेक्ष्य में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन पर आरोप लगाया था कि इन दोनों देशों ने विकसित देशों से अरबों डॉलर की मदद लेने की शर्त पर समझौते पर दस्तखत किए हैं।

लिहाजा यह समझौता अमेरिका के आर्थिक हितों को प्रभावित करने वाला है। यही नहीं, ट्रंप ने आगे कहा था कि भारत ने 2020 तक अपना कोयला उत्पादन दोगुना करने की अनुमति भी ले ली है। वहीं चीन ने कोयले से चलने वाले सैकड़ों बिजलीघर चालू करने की शर्त पर दस्तखत किए हैं। साफ है यह समझौता अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने वाला है। ट्रंप ने यहां तक कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की 'हरित जलवायु निधि अमेरिका से धन हथियाने की साजिश है। तभी ट्रंप की इस सोच ने तय कर दिया था कि अमेरिका अब वैश्विक समस्याओं के प्रति उदार रुख नहीं अपनाएगा। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को करारा जवाब देते हुए कहा था कि 'भारत प्राचीनकाल से ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाता चला आ रहा है। हमारे 5000 साल पुराने शास्त्र पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहे हैं। हम 40 करोड़ एलईडी बल्ब घर-घर पहुंचाकर हजारों मेगावाट बिजली बचाकर कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में लगे हैं।' यहां यह स्पष्ट करना मुनासिब होगा कि पेरिस समझौते के बाद 2015 में भारत को हरित जलवायु निधि से कुल 19000 करोड़ रुपये की मदद मिली थी।

इसमें अमेरिका का हिस्सा महज 600 करोड़ रुपये था। ऐसे में ट्रंप का यह दावा नितांत खोखला था कि भारत को इस निधि से अमेरिका के जरिए बड़ी मदद मिल रही है। साफ है कि ट्रंप के इस पर्यावरण संरक्षण विरोधी मानसिकता के जवाब में ही वित्तीय अंतर को भरने के लिए इस सम्मेलन में विकासशील देश अन्य विकसित देशों से धन एवं तकनीक की मदद दिए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए दोषी तो औद्योगिक और प्रौद्योगिकी उत्पादन करने वाले अमेरिका जैसे विकसित देश हैं, किंतु इसका नुकसान बढ़ते तापमान के चलते नेपाल जैसे छोटे देश उठाने को मजबूर हो रहे हैं। इसीलिए नेपाल में जब बाढ़ के रूप में भीषण प्राकृतिक आपदा आई थी, तब नेपाल ने इस जलवायु आपदा में हुए नुकसान की पूर्ति की मांग भी विकसित देशों से की थी।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

मंथन

डॉ. मोनिका शर्मा



मृत्युदंड की सजा - स्पष्ट दृष्टिकोण भारत का अधिकार

भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी बर्बर अपराध को अंजाम देने वाला अपराधी बच निकलने के बाद फिर अपराध करने से नहीं चूकता। हमारे देश में तो ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। सामूहिक बलात्कार, निर्मम हत्या, आतंकी गतिविधियों तक में यह लिप्तता देखने को मिली है। यही वजह है कि समाज का बड़ा एक वर्ग जघन्य और अत्यंत क्रूर अपराधों में कठोरतम सजा देने को सही ठहराता है। कठोर दंड को सामाजिक परिवेश में न्याय की भावना और अपराधियों में भय पैदा करने के लिए आवश्यक मानता है। विशेषकर निर्मम अपराधों के मामलों में पीड़ित परिवार यह महसूस करते हैं कि जीवनभर की सजा पर्याप्त बजाय मृत्युदंड मिलना ही सही न्याय है। हाल में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमारे देश का मृत्युदंड पर रोक लगाने से जुड़े मसौदा प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करना बर्बर मानसिकता के प्रति स्पष्ट रुख रखने की बानगी बना। समाज-परिवार और देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में अपनी संप्रभु सोच को स्पष्ट किया। असल में इस प्रस्ताव में मृत्युदंड दिए जाने पर चिंता जताते हुए कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप अपनी न्याय व्यवस्था विकसित करने और उचित कानूनी दंड तय करने का अधिकार सभी देशों को है। ऐसे में हमारे देश ने गंभीरतम अपराधों के लिए मृत्युदंड का विकल्प बनाए रखने का निर्णय लिया है। यह पहली बार नहीं है जब भारत ने इस मोर्चे पर अपनी बात स्पष्टता से रखी है। वर्ष 2016, 2018 और 2024 में भी दुनियाभर में फांसी की सजा पर रोक लगाने संबंधी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के विरुद्ध ही मतदान किया था। भारत, ठोस तर्कों के साथ देश की कानूनी व्यवस्था के अनुसार इस मसौदे के खिलाफ अपनी रखता आया है। इस वर्ष मेक्सिको की ओर से पेश किया गया यह प्रस्ताव सभी देशों से मृत्युदंड को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने का अनुरोध लिए था। इसमें जिन देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है, उनसे इसे दोबारा लागू नहीं करने की अपील भी शामिल थी। गौरतलब है कि 193 सदस्य देशों में से 133 ने इस प्रस्ताव समर्थन किया है। वहीं, 33 देशों ने इसके खिलाफ अपनी वोट किया। 16 देश संयुक्त राष्ट्र महासभा में आए इस प्रस्ताव के मतदान से अनुपस्थित रहे। वस्तुतः हर देश की अपनी एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। आपराधिक मामलों की जांच और सजा के नियम कायदे होते हैं। देश में बढ़ रहे बर्बर अपराधों के आंकड़े बताते हैं कि सजा देने के मामले में सख्ती आवश्यक है। बावजूद इसके हमारे देश में केवल दुर्लभतम मामलों में ही फांसी की सजा सुनाई जाती है। ऐसे में अपने देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और संप्रभु अधिकारों के प्रति समझौता नहीं किया जा सकता। इसी के चलते मृत्युदंड की सजा के विरुद्ध पूरी दुनिया में कोई आम सहमति बनना वाकई मुश्किल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी इस पर चिंता जताई गई कि मृत्युदंड देने के विचार को सीमित करने के प्रयासों को बल देने के बावजूद 2025 में फांसी दिए जाने के दर्ज मामले बढ़े हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल दुनिया के 17 देशों में करीब 2,707 लोगों को डेथ पैनल्टी की सजा दी गई। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर सभी देशों को साथ लाने की कोशिशें की जा रही हैं। समझना जरूरी है कि अमानवीय अपराध के लिए दी गई कठोर सजा को केवल अपराधी के मानवाधिकारों से जोड़ना उचित नहीं। इस आपराधिक प्रवृत्ति के शिकार हुए लोगों और उनके परिवारों के मानवाधिकारों को लेकर सोचना भी जरूरी है। साथ ही यह समाज के हर नागरिक एक मन में एक भरोसा पोसने से जुड़ा मामला भी है। यही वजह है कि हमारे देश में सबसे गंभीर अपराधों के लिए यह सर्वोच्च कानूनी सजा देने का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के कई ऐतिहासिक फैसले बताते हैं कि मृत्युदंड अत्यंत क्रूर अपराध और सुधार या पुनर्वास की कोई संभावना न बचने की स्थिति में ही दिया जाता है। देश में आखिरी बार तिहाड़ जेल में 20 मार्च 2020 को फांसी दी गई थी। 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के दोषियों को मृत्युदंड दिया गया था। अमानवीय, क्रूर और निर्ममता की सारी सीमायें पार करने वाली सामूहिक दुष्कर्म की इस घटना ने आमजन को भीतर तक झकझोर दिया था। वैश्विक स्तर पर भी भारत को 'रेप केपिटल' और सबसे असुरक्षित देश तक कहा गया। तब दोषियों को फांसी देने का फैसला पूरे समाज की पीड़ा और आक्रोश के लिए मरहम के समान रहा। इससे पहले 2012 में 26 नवंबर, 2008 को हुए आतंकवादी हमले में शामिल कसाब को फांसी दी गई थी। ऐसे में अपने देश की स्वतंत्र न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने के संप्रभु अधिकार और समाज में विश्वास बनाये रखने हेतु भारत का यह स्पष्ट रुख आवश्यक था।

(लेखिका स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सजगता से दूर होती है चिंता



संकलित

दर्शन

जब तुम चिंता का अनुभव करो, बहुत चिंताग्रस्त हो जाओ, तब इस विधि का प्रयोग करो। इसके लिए क्या करना होगा? जब साधारणतः तुम्हें चिंता घेरती है, तब तुम क्या करते हो? तुम उसका हल ढूंढ़ते हो। उसके उपाय खोजते हो। लेकिन ऐसा करके तुम और भी चिंताग्रस्त हो जाते हो। तुम उपद्रव को बढ़ा लेते हो, क्योंकि विचार से चिंता का समाधान नहीं हो सकता है। विचार के द्वारा चिंता का विसर्जन नहीं हो सकता है, क्योंकि विचार स्वयं एक तरह की चिंता है। यह विधि बहुत आसान है। यह कहती है कि चिंता के साथ कुछ मत करो। सिर्फ सजग हो जाओ। मैं तुम्हें एक दूसरे जेन गुरु बोकोजू के संबंध में एक पुरानी कहानी सुनाता हूं। वह एक गुफा में अकेले रहते थे, बिल्कुल अकेले। लेकिन दिन में या कभी-कभी रात में भी वह जोरों से कहता थे, 'बोकोजू'। यह उनका अपना नाम था। और फिर वह खुद कहते, 'हां महोदय, मैं मौजूद हूं।' जबकि वहां कोई दूसरा नहीं होता था। उनके शिष्य उससे पूछते थे, 'क्यों आप अपना ही नाम पुकारते हैं और फिर खुद कहते हैं, हां, मैं उपस्थित हूं?' बोकोजू ने कहा, 'जब भी मैं विचार में डूबने लगता हूं तो मुझे सजग होना पड़ता है। इसीलिए मैं अपना नाम पुकारता हूं। जिस क्षण मैं बोकोजू कहता हूं और कहता हूं कि हां महाशय, मैं मौजूद हूं, उसी क्षण विचारणा, चिंता विलीन हो जाती है।' फिर अपने अंतिम दिनों में, आखिरी दो-तीन वर्षों में उन्होंने कभी अपना नाम नहीं पुकारा और न ही यह कहा कि हां, मैं मौजूद हूं।

पांच मिनट का जीवन



संकलित

प्रेरणा

एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए व्यक्ति से पानी मांगा, बिना एक क्षण गंवाए उसने पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आये हैं लेकिन चूंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूं। यह कहकर यमराज ने एक डायरी देकर उस आदमी से कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। इसमें तुम जो भी लिखोगे वही हो जाएगा लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो उसने देखा कि पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहां लिख दिया कि उसके पड़ोसी की लॉटरी न निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है, तो उसने लिख दिया कि उसका दोस्त चुनाव हार जाए। इस तरह, वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ से डायरी ले ली और कहा वत्स तुम्हारा पांच मिनट का समय पूरा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपने पूरे 5 मिनट का समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया, अंततः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया लेकिन सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था।

सटाका



आज की पाती

नदियों को प्रदूषित करने पर सख्त कार्रवाई जरूरी

आजकल नदियों में प्रदूषण बढ़ने की खबर सुर्खियों में है। रायपुर और इसके साथ लगते क्षेत्रों में जहां भी नदियां बह रही है, उसमें पानी की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। इसके लिए अदालत ने भी कहा है कि करोड़ों रुपए इसकी सफाई पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें प्रदूषण बढ़ रहा है। कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए प्रदूषण के जिम्मेदार लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा और संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी इसकी वसूली की जाएगी। क्योंकि सरकारें और संबंधित विभाग नदियों की सफाई के प्रति दुलमुल रवैया अपनाते हैं। तभी तो कुछ तत्व बेखौफ होकर इन्हें प्रदूषित करते हैं। नदियों को प्रदूषित करने पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। - पवन गहलोत, रोहतक

ट्रेंड

बेहतरीन तालमेल



कुलगाम में लश्कर के चोटी में मौजूद आखिरी सक्रिय स्थानीय आतंकवादी, लतीफ भट को मार गिराया गया। उससे एक दिन पहले, कुलगाम में ही उसके एक साथी आतंकवादी, उमर निसार को भी मार गिराया गया था। इस पूरे ऑपरेशन में बेहतरीन तालमेल देखने को मिला।
- अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

स्केटर सृष्टि को बधाई



महाराष्ट्र की युवा स्केटर सृष्टि शर्मा ने लिम्बो स्केटिंग में 50 मीटर की दूरी सिर्फ 6.86 सेकंड में तय करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हमें सृष्टि के कौशल और प्रदर्शन पर गर्व है। सृष्टि को हार्दिक बधाई!
- देवेंद्र फडणवीस, सीएम, महाराष्ट्र

अनुशासनहीनता अस्वीकार्य



पुलिस की वर्दी में अनुशासनहीनता और कदाचार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। पुलिस बल में अनुशासन, जवाबदेही और ईमानदारी सर्वोपरि है। 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए हैं। - डॉ. मोहन यादव, सीएम, मध्यप्रदेश

मोदी का वादा

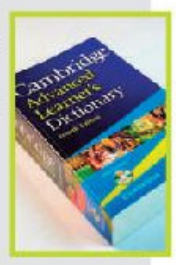


मोदी जी ने महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए है कि आम आदमी की थाली छोटी होती जा रही है, जेबें खाली हो रही है, और घर का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है। 2014 में महंगाई कम करने का वादा, 2026 में लोगों की जेबों पर डाका।
- मल्लिकार्जुन खड़गे, अध्यक्ष, कांग्रेस

करंट अफेयर

कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 'ह्यूमन' को चुना वर्ष 2026 का शब्द

कृत्रिम मेधा (एआई) को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच 'कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 'ह्यूमन' डिक्शनरी' ने 2026 के उस शब्द के चयन के लिए 15वीं सदी की ओर रुख किया है, जो मौजूदा सांस्कृतिक और सामाजिक माहौल को सबसे बेहतर ढंग से बयां करता है। डिक्शनरी ने 'ह्यूमन' (मानव) को 2026 का शब्द चुना है। यह चयन केवल अतीत की ओर लौटने का संकेत नहीं है, बल्कि एआई के कारण मशीनों और इंसानों के बीच धुंधली होती सीमाओं को लेकर चल रही बहस का भी प्रतिबिंब है। डिक्शनरी के शब्दकोश विशेषज्ञ कॉलिनमैकिंटोश ने कहा, ' 'एआई हमारे मानव होने के अर्थ को लेकर बातचीत का तरीका बदल रहा है। सोचने की क्षमता एआई को सौंपने से इंसान क्या खो सकते हैं, इस चिंता ने हमें एआई पर अपनी निर्भरता के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर किया है। यह चिंता बड़े गणितज्ञों से लेकर छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों तक में है।' लैटिन भाषा के शब्द 'ह्यूमनस' से बना शब्द 'ह्यूमन' 1450 के दशक से इस्तेमाल में है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार, इसका अर्थ है- ऐसे गुणों, कमियों और भावनाओं से युक्त होना, जो इंसानों में होती हैं और जो उन्हें देवताओं, जानवरों या मशीनों से अलग करती हैं।



ऑफ बीट

अंटार्कटिका में शूज के निशान भी पहुंचा सकते हैं नुकसान

जंगलों और प्राकृतिक क्षेत्रों में घूमने जाने वाले लोगों को आमतौर पर सलाह दी जाती है कि वे वहां केवल अपने पैरों के निशान छोड़कर आएं। हालांकि, एक नए अध्ययन में सामने आया है कि अंटार्कटिका में पैरों के निशान भी दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनमें ऐसे बदलाव ला सकते हैं, जिनकी भरपाई संभव नहीं है। अंटार्कटिका में दुनिया के कुछ सबसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद हैं। इनमें मैकमुर्डो ड्राई वैलीज की विशाल बर्फ-मुक्त भूमि की स्थायी रूप से जमी मिट्टी भी शामिल है। यह पृथ्वी के सबसे शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में से एक है। कठोर जलवायु परिस्थितियों के बावजूद यहां बर्फ से जमी मिट्टी की परतों में विशिष्ट सूक्ष्मजीव समुदाय और नेमेटोड, टार्डिग्रेड तथा रोटिफर जैसे छोटे अकशेरुकी जीव पाए जाते हैं। ये जीव रेत के कणों के आसपास मौजूद पानी की बेहद पतली परतों में जीवित रहते हैं। अंटार्कटिका के पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाता है। इसके तहत वहां जाने से पहले शूज और अन्य उपकरणों की व्यापक जांच, सफाई और संक्रमणमुक्त करने के नियम लागू हैं। हालांकि, इन नियमों का मुख्य उद्देश्य बाहरी आक्रामक प्रजातियों को अंटार्कटिका में पहुंचने और फैलने से रोकना है।



मेथीपुरा में शराब तस्करी को लेकर गुजरात विजिलेंस टीम की कार्रवाई, टीम पर हमले का आरोप

नाकाबंदी तोड़कर भागे तस्करों के वाहनों का पीछा कर तीन लग्जरी गाड़ियां कब्जे में लीं, एक पुलिसकर्मी घायल; पांच अन्य वाहनों की तलाश जारी

रेवदर (शकूर खान रंगरेज)। राजस्थान से गुजरात में अवैध शराब तस्करी के मामले में मंडार थाना क्षेत्र के सीमावर्ती मेथीपुरा गांव में गुजरात विजिलेंस टीम की कार्रवाई के दौरान पुलिस पर हमले का मामला सामने आया है। मुखबिर की सूचना पर गुजरात पुलिस की विजिलेंस टीम ने दांतीवाड़ा के डेरी के पास नाकाबंदी कर शराब तस्करी में संदिग्ध वाहनों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वाहन चालक नाकाबंदी तोड़कर वापस राजस्थान की ओर भाग निकले। पीछा करने के दौरान पुलिस टीम पर वाहन चढ़ाने का आरोप है, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया।

जानकारी के अनुसार गुजरात विजिलेंस टीम को राजस्थान से गुजरात की ओर अवैध शराब की बड़ी खेप पहुंचने की सूचना मिली थी। इस पर टीम ने दांतीवाड़ा के डेरी के पास नाकाबंदी कर वाहनों को रोकने का प्रयास किया। लेकिन वाहन चालक पुलिस को चकमा देकर वापस मेथीपुरा गांव की ओर भागने लगे। इस दौरान पुलिसकर्मी को वाहन से टक्कर मारकर घायल करने का भी आरोप सामने आया है।

गुजरात विजिलेंस टीम ने राजस्थान पुलिस से शराब तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों को सुपुर्द करने का आग्रह किया, लेकिन मौके पर सहमति नहीं बनने के बाद गुजरात पुलिस के अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया। बताया जा रहा है कि उच्च स्तर पर राजस्थान एवं गुजरात के गृह विभागों के बीच वार्ता के बाद कार्रवाई आगे बढ़ी। आखिरकार गुजरात विजिलेंस टीम तीन वाहनों को अपने कब्जे में लेकर गुजरात रवाना हुई। हालांकि, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। समाचार लिखे जाने तक टीम पांच अन्य वाहनों को भी कब्जे में लेने के प्रयास में जुटी हुई थी।

लंबे समय से शराब तस्करी की आशंका

गुजरात विजिलेंस टीम के अधिकारियों के अनुसार मेथीपुरा क्षेत्र से गुजरात में लंबे समय से अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी। इस संबंध में समय-समय पर पुलिस कार्रवाई भी हुई है। लेकिन बड़े स्तर पर तस्करी की सूचना मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने विशेष कार्रवाई की।

आबकारी थाने और पुलिस चौकी की मौजूदगी पर उठे सवाल

राजस्थान सरकार ने अवैध शराब परिवहन एवं तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से क्षेत्र में आबकारी थाना स्थापित किया है, वहीं सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस चौकी भी मौजूद है। इसके बावजूद गुजरात पुलिस की विजिलेंस टीम द्वारा लगातार अवैध शराब के वाहनों पर कार्रवाई किए जाने तथा मेथीपुरा में गोदाम तक पहुंचने के घटनाक्रम ने स्थानीय आबकारी एवं पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों में भी घटना को लेकर चर्चा बनी रही। लोगों का सवाल है कि सीमावर्ती क्षेत्र में इतनी बड़ी मात्रा में शराब तस्करी की गतिविधियां संचालित होने के बावजूद स्थानीय पुलिस एवं आबकारी विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली? पुलिस चौकी एवं आबकारी व्यवस्था की मौजूदगी के बावजूद तस्करी पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पाना अब चर्चा का विषय बना हुआ है।

जयपुर में 4 दिसंबर से होगा लोकमंथन-2026

'हम भारत के लोग' रहेगी थीम; मुख्यमंत्री भजनलाल ने किया भूमि-पूजन



जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के जवाहर कला केंद्र में तीन दिवसीय लोकमंथन-2026 का गुरुवार को विधि-विधान के साथ भूमि पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सीएम ने हवन में पूर्णाहुति अर्पित की। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी आदि मौजूद रहे। 'हम भारत के लोग' थीम पर आधारित लोकमंथन का आयोजन 4 से 6 दिसंबर तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल ने जवाहर कला केंद्र में लोकमंथन-2026 की स्वागत समिति की बैठक को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की गौरवशाली धरा पर लोकमंथन-2026 का आयोजन होना प्रदेश के लिए बड़े गौरव और सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि राजस्थान अपनी ऐतिहासिक विरासत, लोक कलाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक विविधता के लिए देश-दुनिया में विशिष्ट पहचान रखता है।

'हम भारत के लोग' थीम पर होगा राष्ट्रीय विमर्श

इस बार लोकमंथन की थीम 'हम भारत के लोग' है। आयोजन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं और राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर व्यापक विमर्श करना है। इसमें देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले विचारक, चिंतक, साहित्यकार, बुद्धिजीवी और संस्कृतिकर्मी भारतीय समाज की सांस्कृतिक चेतना, लोकजीवन और राष्ट्रीय चिंतन के विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा करेंगे।

अवैध बजरी खनन और ओवरलोड परिवहन पर पुलिस का शिकंजा, 4 ट्रेलर और 4 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

रोहट में दो आरोपी गिरफ्तार, एसआईटी ने ड्रोन से किया अवैध खनन क्षेत्रों का सर्वे







पाली, मनीष राठौड। जिले में अवैध बजरी एवं मिट्टी खनन और ओवरलोड परिवहन के खिलाफ पाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 4 ट्रेलर और 4 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की हैं। वहीं, रोहट थाना पुलिस ने अवैध खनन के दो मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के साथ एसआईटी ने नदी क्षेत्रों में ड्रोन से सर्वे कर अवैध खनन की संभावित जगहों को चिन्हित किया है। पाली पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देशन में अवैध खनन और खनिज परिवहन की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रोहट थाना पुलिस ने अवैध खनन के दो मामले दर्ज कर दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की। पुलिस ने मामले में सोहनलाल निवासी दलपतगढ़ और मूलाराम निवासी निम्बली ब्राह्मनान को गिरफ्तार किया। वहीं जैतपुर थाना पुलिस ने वैध माइनिंग लीज से ओवरलोड बजरी परिवहन करते पाए जाने पर चार ट्रेलर एमवी एक्ट के तहत जब्त किए। इसके अलावा सदर पाली थाना पुलिस ने अवैध बजरी से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली तथा औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने अवैध मिट्टी से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की।

ड्रोन से नदी क्षेत्रों का सर्वे, अवैध खनन की जगहें चिन्हित

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश चौधरी और वृताधिकारी अमरसिंह रतनू के सुपरविजन में गठित एसआईटी ने खनन एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से रोहट क्षेत्र का निरीक्षण किया।

टीम ने बागड़िया, मंडली दर्जीयान, कलाली और रामपुरा क्षेत्रों में जोजरी नदी, रेडियो नदी और लूणी की सहायक नदियों का निरीक्षण किया। एसआईटी ने ड्रोन कैमरों की मदद से नदी क्षेत्रों का सर्वे कर अवैध खनन की संभावित जगहों को चिन्हित किया। इन स्थानों पर आगे आकस्मिक जांच एवं कार्रवाई की जाएगी।

अवैध खनन की सूचना देने की अपील

पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन से जुड़ी जानकारी खनन विभाग को भी उपलब्ध कराई है। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि अवैध खनन या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस के व्हाट्सएप नंबर 9251255006 या 9414220940 पर दें। पुलिस के अनुसार सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

छोटी सजा पर सरकारी अधिकारी-कर्मचारी का प्रमोशन नहीं रोक सकते

हाईकोर्ट की लार्जर बैंच ने कहा-एक गलती की दो सजा नहीं हो सकती; कानूनी बिंदू किया तय

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की लार्जर बैंच ने एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदू तय करते हुए कहा कि किसी भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को मिली छोटी सजा (परिनिंदा-बिना संचयी प्रभाव के एक वेतन वृद्धि रोकना) के आधार पर उसके प्रमोशन पर विचार करने से इनकार नहीं किया जा सकता हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल, जस्टिस समीर जैन और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की लार्जर बैंच ने कहा कि किसी भी सरकारी कार्मिक को पिछले 7 साल में मिली छोटी सजा प्रमोशन पर विचार नहीं करने अथवा रोकने का आधार नहीं बन सकती हैं। बैंच ने कहा- जब राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के तहत कार्मिक को किसी गलती पर परिनिंदा (लिखित चेतावनी) और बिना संचयी प्रभाव के एक वेतन वृद्धि रोकने (सजा की अवधि खत्म होने पर रोकी हुई वेतन वृद्धि दे दी जाती हैं।) की सजा मिलती है, तो फिर उसका प्रमोशन रोककर उसे दूसरी सजा नहीं दी जा सकती हैं। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा- एक गलती की दो सजा नहीं हो सकती हैं।



डिवीजन बैंच ने भेजा था रेफरेंस

दरअसल, यह पूरा मामला पुलिस निरीक्षक अजयकांत रतूड़ी से जुड़े विवाद से सामने आया था। 23 नवंबर 1996 को उपनिरीक्षक पद पर नियुक्त रतूड़ी 30 सितंबर 2013 को निरीक्षक बने। सेवाकाल के दौरान उन्हें 16 दिसंबर 2017, 29 जून 2019 और 18 जून 2021 को परिनिंदा की तीन लघु सजाएं मिलीं। इसके बाद आरपीएस (जूनियर स्केल) में पदोन्नति के विचार को लेकर विवाद खड़ा हुआ। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने माना कि छोटी सजाए उनके प्रमोशन पर विचार करने से नहीं रोक सकती हैं लेकिन सरकार इस आदेश के खिलाफ डिवीजन बैंच में चली गई। डिवीजन बैंच ने पाया कि पिछले 7 सालों में मिले लघु दंडों के आधारित पदोन्नति पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अलग-अलग न्यायिक मत हैं। इसलिए डीबी ने 27 अगस्त 2025 को इसे लार्जर बैंच को रेफर कर दिया।

सर्कुलर नहीं ले सकते नियम का स्थान

कोर्ट ने कहा- सरकारी सर्कुलर केवल नियमों के खालीपन को भर सकते हैं, लेकिन वैधानिक (विधानसभा से पारित) नियमों में बदलाव नहीं कर सकते और न ही उनसे ऊपर जा सकते हैं। सीसीए नियमों में परिनिंदा या वेतनवृद्धि रुकने पर प्रमोशन से अयोग्य ठहराने की कोई सीधी रोक नहीं है। बिना विचार किए केवल सर्कुलर के आधार पर प्रमोशन रोकना अप्रत्यक्ष रुप से प्रमोशन रोकने की सजा देना होगा जबकि सजा बढ़ाने के लिए नियमों में तय प्रक्रिया और समयसीमा मौजूद है।

रिकॉर्ड की समीक्षा करने पर रोक नहीं

कोर्ट ने साफ किया कि प्रमोशन के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) पूरे सेवा रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में सात साल के भीतर मिली सजा को देख सकती है, यह इसलिए जरुरी है ताकि यह परखा जा सके कि कर्मचारी प्रशासनिक दक्षता के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता और उपयुक्तता की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। लेकिन सात साल के भीतर मिली परिनिंदा और लघु सजा अपने-आप प्रमोशन से वंचित करने अथवा अयोग्य मानने का आधार नहीं बन सकती हैं।

जयपुर- जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना आज

जिला परिषद के 57 वार्डों की काउंटिंग के लिए 98 टेबिल लगाई; 22 पंचायत समितियों के लिए 22 रूम



जयपुर। जयपुर जिला परिषद और पंचायत समितियों सदस्यों के लिए कल वोटो की काउंटिंग होगी। भवानी निकेतन परिसर में मतगणना होगी। हर वार्ड की ईवीएम के वोटों की काउंटिंग शुरू होने से पहले उसी वार्ड के पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी। जिला परिषद के 57 वार्डों के लिए 5 और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 22 वोटिंग काउंटिंग रूम बनाए है। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया- जिला परिषद सदस्यों के वोटो की काउंटिंग के लिए कुल 5 कमरे निर्धारित किए हैं। सभी 57 वार्डों की मतगणना के लिए कुल 98 टेबल निर्धारित की गई हैं। वार्ड संख्या 1 से 10 तक के 10 वार्डों की काउंटिंग होगी, जिसके लिए 18 टेबल लगाई जाएगी। इसी तरह वार्ड संख्या 15 से 26 तक के 12 वार्डों के लिए 19 टेबल, वार्ड संख्या 27 से 37 तक के 11 वार्डों के लिए 21 टेबल और वार्ड संख्या 38 से 50 तक के 13 वार्डों के लिए 20 टेबल निर्धारित की हैं।

देवउठनी एकादशी का व्रत आज,गोविंददेवजी मंदिर में होगा तुलसी विवाह

भक्तों को चलना होगा 2 से 3 किलोमीटर; जानें- दर्शन और पार्किंग की व्यवस्था

जयपुर। देवउठनी एकादशी पर गोविंददेवजी मंदिर में 21 नवंबर को भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। इसके तहत भक्तों को दर्शन के बाद मंदिर में रुकने नहीं दिया जाएगा। मंदिर में प्रवेश मुख्य द्वार से होगा और बाहर निकलने की व्यवस्था जय निवास बाग की ओर से रहेगी। भक्तों के लिए जूते-चप्पल पहनकर और बिना जूते-चप्पल के आने वालों की अलग-अलग लाइनें बनाई जाएगी। मंदिर प्रशासन ने भक्तों से जूते-चप्पल और हेलमेट अपने वाहन में ही रखने की अपील की है। सूर्यसिद्धान्तीय पंचांग जयादित्य पंचांग के अनुसार- 19 नवंबर को देर रात 2 बजकर 3 मिनट पर दशमी तिथि समाप्त होगी और एकादशी शुरू होगी। सूर्योदय के समय दशमी तिथि नहीं होने के कारण एकादशी का व्रत 20 नवंबर शुक्रवार को रखा जाएगा। इसी दिन तुलसी विवाह भी होगा। देवउठनी एकादशी पर भगवान श्रीहरि को जगाने की परंपरा है। इस दिन रात में भगवान का अभिषेक कर उनकी स्तुति की जाती है। वहीं गोविंददेवजी मंदिर में विशेष दर्शन 21 नवंबर को होंगे।



जूते-चप्पल पहनकर आने वालों के लिए अलग व्यवस्था

मंदिर प्रशासन के अनुसार- दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को दो अलग लाइनों से प्रवेश दिया जाएगा। जूते-चप्पल पहनकर आने वाले भक्त मंदिर के बाहर बने रैंप से दर्शन कर सकेंगे। वहीं बिना जूते-चप्पल आने वाले भक्त मंदिर छावन में दर्शन करेंगे। सभी भक्तों को दर्शन के बाद जय निवास बाग की ओर से बाहर निकाला जाएगा। जय निवास बाग से मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। कंवर नगर और ब्रह्मपुरी की ओर से आने वाले भक्त जय निवास उद्यान और जनता मार्केट होते हुए मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच सकेंगे। दर्शन के बाद मंदिर श्री चिंताहरण हनुमानजी की ओर से बाहर निकल सकेंगे। भक्तों को करीब 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ सकता है। ऐसे में पानी की बोतल साथ लाने की सलाह दी गई है।

रामनिवास बाग और चौगान स्टेडियम में पार्क करें वाहन

मंदिर प्रशासन ने भक्तों से अपने वाहन रामनिवास बाग पार्किंग या चौगान स्टेडियम पार्किंग में खड़े करने के लिए कहा है। साथ ही जूते-चप्पल और हेलमेट वाहन में ही रखने की अपील की है। हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और सांस की परेशानी से जूझ रहे लोगों को भीड़ में मंदिर नहीं आने की सलाह दी गई है। भक्तों से बैग, थैले, लेडीज पर्स और कीमती आभूषण पहनकर नहीं आने के लिए भी कहा गया है। मंदिर परिसर में कोई संदिग्ध व्यक्ति या लावारिस सामान दिखाई देने पर मंदिर प्रशासन या पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है।

64 विला-कॉटेज खरीद मामले में IAS-शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ीं

हाईकोर्ट का जांच पर रोक लगाने से इनकार, कहा- पहले सरकार का जवाब आने दें



जयपुर। 64 विला-कॉटेज खरीद मामले में IAS शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार सुबह 10:40 बजे शिखर अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के लिए कहा है। अब 18 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। शिखर ने 17 नवंबर को अपने खिलाफ एसीबी जांच को चुनौती दी थी। इधर, एसीबी ने 18 नवंबर को IAS शिखर अग्रवाल सहित गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड (अनंता रिसॉर्ट्स) के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एसीबी ने मामले में गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य को भी आरोपी बनाया है।

एसीबी नोटिस जारी कर करेगी पूछताछ

एसीबी ने मामले में 20 विभागों से रिकॉर्ड-डॉक्यूमेंट मांगे थे। मामले की जांच एएसपी प्रशांत कौशिक को दी गई है।

एग्रीगेटर नीति लागू करने में राजस्थान देश में प्रथम, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की सराहना

चालक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल पंजीकरण और नियामकीय जवाबदेही के प्रावधानों को बताया महत्वपूर्ण

जयपुर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान सरकार द्वारा केंद्र सरकार की मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 को राज्य में लागू करने की पहल की सराहना करते हुए राजस्थान को देश का पहला राज्य बताया है, जिसने इन दिशा-निर्देशों को पूर्ण रूप से लागू किया है। उन्होंने अन्य राज्यों से भी राजस्थान की तर्ज पर एग्रीगेटर नीति को अपनाने का आह्वान किया। गडकरी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित 'RIDE: A Showcase of Aggregator and Delivery Services' कार्यक्रम में उन्होंने राजस्थान को देश का पहला राज्य बताया, जिसने केंद्र सरकार की मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 को राज्य में पूर्ण रूप से लागू किया है। कार्यक्रम में देश में एग्रीगेटर एवं डिलीवरी सेवाओं के माध्यम से रोजगार सृजन, आजीविका के अवसरों, चालक कल्याण तथा सुरक्षित और समावेशी परिवहन व्यवस्था के विकास पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2025 को जारी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस के अनुरूप राजस्थान ने नियम बनाकर उन्हें लागू किया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इन दिशा-निर्देशों को आंशिक रूप से लागू किया गया है। राजस्थान की इस पहल से अन्य राज्यों को भी एग्रीगेटर सेवाओं के नियमन के लिए दिशा मिलेगी।



चालक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को दिया विशेष महत्व

राजस्थान के एग्रीगेटर नियमों में चालक एवं डिलीवरी पार्टनर्स के हितों और सामाजिक सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। नियमों के प्रावधानों में चालकों के लिए स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के प्रावधानों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही वाहन चालकों की पहचान एवं दस्तावेजों का सत्यापन, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण-पत्र, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं की अनुपालना अनिवार्य की गई है। नियमों के माध्यम से एग्रीगेटर कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ यात्रियों की सुरक्षा, शिकायतों के निस्तारण और परिवहन सेवाओं में पारदर्शिता को भी प्राथमिकता दी गई है।

प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने दिया राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रलाइज्ड पोर्टल का सुझाव

कार्यक्रम में राजस्थान की ओर से प्रमुख शासन सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, भवानी सिंह देथा ने राज्य में एग्रीगेटर सेवाओं के नियमन एवं डिजिटल पंजीकरण के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र की गाइडलाइंस के अनुरूप राजस्थान मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम रूल्स-2025 लागू किए गए हैं। इन नियमों के माध्यम से एग्रीगेटर कंपनियों के पंजीकरण, लाइसेंस, वाहनों के पंजीयन, चालक संबंधी व्यवस्थाओं तथा नियामकीय अनुपालना के लिए स्पष्ट व्यवस्था विकसित की गई है। कार्यक्रम में उप परवहन आयुक्त वीरेन्द्र सिंह राठोड व अलवर आरटीओ रविन्द्र सिंह भी शामिल हुए ।

राजस्थान ने दिसंबर 2025 में ही लागू किए एग्रीगेटर नियम

भवानी सिंह देथा ने बताया की राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 के अनुरूप 30 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर स्कीम रूल्स-2025 लागू किए, जिन्हें 31 दिसंबर 2025 को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इन नियमों के माध्यम से राज्य में एग्रीगेटर कंपनियों, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स संस्थाओं के नियमन के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। राजस्थान की नीति की विशेषता यह है कि इसमें केवल यात्री परिवहन सेवाओं को ही नहीं, बल्कि डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं को भी नियामकीय दायरे में शामिल किया गया है। नियमों के तहत राजस्थान में न्यूनतम 25 संबद्ध मोटर वाहन संचालित करने वाली पात्र संस्थाओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। लाइसेंस की वैधता पांच वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही कंपनियों के लिए राज्य में कॉरपोरेट अथवा शाखा कार्यालय स्थापित करने तथा अनुपालना अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान भी किया गया है।

निजी मोटरसाइकिलों को एग्रीगेटर सेवाओं से जोड़ने की पहल

नॉन-ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिलों को एग्रीगेटर एवं डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से सेवाओं से जोड़ने का प्रावधान है। हालांकि, राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में इस प्रावधान की समीक्षा एवं संशोधन की प्रक्रिया विचाराधीन है। इस व्यवस्था का उद्देश्य निजी वाहन स्वामियों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के साथ यात्रियों को किफायती परिवहन विकल्प प्रदान करना है।

राजस्थान में लगभग 4.66 लाख वाहनों का एग्रीगेटर फ्लीट

उपलब्ध एग्रीगेटर फ्लीट आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान से संबंधित प्रमुख एग्रीगेटर कंपनियों के पास कुल 4,65,658 वाहनों का फ्लीट है। इसमें दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहन शामिल हैं।

कंपनीवार उपलब्ध आंकड़े इस प्रकार हैं-

एग्रीगेटर फ्लीट आंकड़ों का विवरण

राजस्थान से संबंधित प्रमुख एग्रीगेटर कंपनियों के पास कुल 4,65,658 वाहनों का फ्लीट उपलब्ध है, जिसमें 3,98,792 दोपहिया, 37,767 तिपहिया और 29,099 चारपहिया वाहन शामिल हैं। कंपनीवार विवरण के अनुसार, **Ola** के पास कुल 82,733 वाहन हैं, जिनमें 62,272 दोपहिया, 11,395 तिपहिया और 9,066 चारपहिया वाहन शामिल हैं। **ber** के पास कुल 74,978 वाहन हैं, जिनमें 57,420 दोपहिया, 8,778 तिपहिया और 8,780 चारपहिया वाहन शामिल हैं। **Rapido** के पास कुल 2,97,947 वाहन हैं, जिनमें2,75,100 दोपहिया, 15,094 तिपहिया और 7,753 चारपहिया वाहन शामिल हैं।

सियोल घोषणापत्र पर मुख्य सचिव ने किए हस्ताक्षर



सियोल/जयपुर। राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (आईआईएएस) के अध्यक्ष के रूप में गुरुवार को सियोल घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। कोरिया गणराज्य के सियोल में आयोजित आईआईएएस 2026 सम्मेलन के दौरान उन्होंने लोक प्रशासन संस्थाओं और भागीदार संगठनों के प्रमुखों के साथ आर्थिक विकास को लोगों के जीवन में स्थायी सुधार से जोड़ने की साझा प्रतिबद्धता जताई। घोषणापत्र की पांच प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए वी. श्रीनिवास ने कहा कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए सरकार की सक्रिय भूमिका के साथ उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग जरूरी है। उन्होंने नीति निर्माण में नागरिकों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्मिकों की सार्थक भागीदारी पर भी जोर दिया। सामाजिक नवाचार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक समस्याओं के सफल समाधानों की पहचान कर उन्हें व्यापक स्तर पर अपनाने की जरूरत है। कानूनी, संस्थागत और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार से इस प्रक्रिया को गति दी जा सकती है। टेक्नोलॉजी और डेटा का जिम्मेदारी से उपयोग भी इन प्रयासों को मजबूत बनाने में सहायक होगा। वी. श्रीनिवास ने संयुक्त अध्ययन, नीतिगत संवाद और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान एवं अनुभवों के आदान-प्रदान के जरिए शोध को प्रशासनिक कामकाज से जोड़ने पर बल दिया।

राजस्थान में होगा चक्रवात अकवान का असर

बादल छाएंगे, तापमान में गिरावट की भी आशंका; माउंटआबू से ठंडा फतेहपुर

जयपुर। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात 'अकवान' का हल्का प्रभाव राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। इस चक्रवात के असर से कोटा संभाग का मौसम बदलने की संभावना है। यहां हल्के बादल छा सकते हैं। उत्तरी हवाओं के असर से बीकानेर संभाग के अलावा शेखावाटी के एरिया में तापमान 2 डिग्री तक गिर सकता है। पिछले 24 घंटे में मौसम साफ रहा और तेज धूप रही। बीकानेर, अजमेर, अलवर, जयपुर, कोटा, फलोदी, सीकर समेत कई शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सबसे ठंडा इलाका सीकर का फतेहपुर रहा।

क्या है चक्रवात अकवान: चक्रवात अकवान का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश में होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक, 19 और 20 नवंबर को तटीय इलाकों में भारी से बेहद भारी बारिश हो सकती है।

राजस्थान में IAS-IPS समेत 300 से ज्यादा भ्रष्ट कार्मिकों पर एक्शन, करीब 70 सस्पेंड-20 बर्खास्त

जयपुर। राजस्थान में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनुशासनहीनता के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए नौकरशाही को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब पद और प्रभाव की आड़ में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को संरक्षण नहीं मिलेगा। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, करीब पौने तीन साल के कार्यकाल में विभिन्न विभागों के 300 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। सबसे अहम बदलाव लंबित अभियोजन स्वीकृतियों को लेकर देखा गया है, जहां पिछली सरकार के समय से अटकी फाइलों को आगे बढ़ाते हुए बड़े पैमाने पर मंजूरी दी गई है।



कार्रवाई का पूरा गणित: निलंबन, बर्खास्तगी और पेंशन पर रोक

सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में सेवाकाल के साथ-साथ सेवानिवृत्त कार्मिकों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया गया है।

अभियोजन स्वीकृति: रिश्वतखोरी, ट्रैप और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी की गई। गौरतलब है कि जुलाई 2024 में विधानसभा में विधायक अतुल भंसाली के सवाल के जवाब में पिछली सरकार के पांच साल में एसीबी मामलों से जुड़े 182 कार्मिकों की अभियोजन स्वीकृति लंबित होने की बात सामने आई थी।

धारा 17-ए में अनुमति: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत 37 मामलों में जांच की अनुमति प्रदान की गई।

निलंबन और बर्खास्तगी: करीब 70 अधिकारियों-कर्मचारियों को निलंबित किया गया, जबकि 20 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया।

पेंशन पर रोक और ट्रैप: 17 अधिकारियों की पेंशन रोकी गई, यानी सेवानिवृत्ति के बाद भी गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं गया। इसके अलावा 100 से अधिक कार्मिकों और अधिकारियों को ट्रैप भी किया गया।

बड़े चेहरों पर शिकंजा: IAS से लेकर IPS तक

मौजूदा दौर में कई वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोपों और मुकदमों को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं-

सुबोध अग्रवाल: जेजेएम घोटाले में रिटायर्ड आइएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को जेल जाना पड़ा।

प्रेमसुख विश्नोइ: 35,000 रुपये की रिश्वत के आरोप में आइपीएस अधिकारी प्रेमसुख विश्नोई को गिरफ्तार किया गया।

मुकेश सोनी: सितंबर में दो करोड़ रुपये की रिश्वत मामले में एएसपी मुकेश सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और उन्हें निलंबित कर दिया गया।

ब्यावर-दौसा-भरतपुर के बीच 277 किमी लंबा बनेगा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू



सवाई माधोपुर। राजस्थान में पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 277 किलोमीटर लंबे ब्यावर-भरतपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की तैयारी तेज हो गई है। करीब 8656 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह फोरलेन एक्सप्रेस-वे प्रदेश के छह जिलों के 210 गांवों से होकर गुजरेगा। परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सवाई माधोपुर जिले में भी इसके लिए 26 गांवों की करीब 330.793 हेक्टेयर जमीन अवाप्त की जाएगी। परियोजना के तहत कुल 210 गांवों के 10,890 खसरों की करीब 2600 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जानी है। एक्सप्रेस-वे जयपुर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर जिलों से होकर गुजरेगा। अलग-अलग जिलों में भूमि अधिग्रहण और परियोजना से जुड़ी प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। इसके पूरा होने पर ब्यावर से भरतपुर तक आवागमन के लिए एक नया और तेज वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा।

जयपुर के राजमहल पैलेस पर पूर्व राजपरिवार का मालिकाना हक बरकरार, राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार और जेडीए की अपील खारिज की



जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के ऐतिहासिक राजमहल पैलेस की संपत्ति को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में पूर्व जयपुर राजपरिवार के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की अपीलें खारिज करते हुए निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें विवादित संपत्ति पर पूर्व राजपरिवार के मालिकाना हक को मान्यता दी गई थी। न्यायमूर्ति अशोक कुमार जैन ने यह आदेश 24 नवंबर 2011 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-5), फास्ट ट्रैक कोर्ट, जयपुर की ओर से दिए गए फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों पर सुनवाई के बाद दिया। यह मामला उस समय काफी चर्चा में आया था, जब आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल जयपुर विकास आयुक्त (जेडीसी) के पद पर तैनात थे। उनके कार्यकाल के दौरान प्रशासन ने लग्जरी राजमहल पैलेस होटल के गेट सील कर दिए थे।

हाईकोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार और जेडीए के लिए झटका माना जा रहा है, जिन्होंने पूर्व राजपरिवार के मालिकाना हक के दावे का विरोध किया था। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी अपील में जो आधार उठाए हैं, उन्हें निचली अदालत के समक्ष ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। अदालत ने यह भी पाया कि सरकार और जेडीए अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने में हुई देरी का संतोषजनक कारण बताने में विफल रहे। ऐसे में अपीलीय अदालत इन नए आधारों पर विचार नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जमाबंदी और खसरा जैसी राजस्व प्रविष्टियां संपत्ति के मालिकाना हक का निर्णायक प्रमाण नहीं हैं। केवल राजस्व रिकॉर्ड में सरकार का नाम दर्ज हो जाने से निजी संपत्ति स्वत: सरकारी जमीन में तब्दील नहीं हो जाती। अदालत ने संपत्ति के मालिकाना हक के निर्धारण में समझौते (कवेनेंट) के प्रावधानों के महत्व पर भी जोर दिया। मामले में पेश किए गए नक्शों से संकेत मिलता है कि प्रिंसेस हाउस एस्टेट में केवल बंगला ही नहीं, बल्कि अन्य इमारतें, आसपास का परिसर, बगीचे और दूसरी सुविधाएं भी शामिल थीं। हालांकि, राज्य सरकार और जेडीए की ओर से दलील दी गई थी कि वर्ष 1958 में जमीन को सरकारी नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था और लंबे समय तक इस प्रविष्टि को चुनौती नहीं दी गई। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कवेनेंट में जिस प्रिंसेस हाउस का उल्लेख है, वह सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर-7 था और राजमहल पैलेस एक अलग संपत्ति है, जो इस समझौते के दायरे में नहीं आती।

इस मामले की सुनवाई के दौरान वर्ष 2016 में तत्कालीन आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने अदालत में माफी भी मांगी थी। उस समय जेडीए आयुक्त के पद पर तैनात शिखर अग्रवाल और तत्कालीन आईएएस अधिकारी मुकेश शर्मा ने अदालत के समक्ष माफी पेश की थी। इसके बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से छूट दे दी गई थी। राजमहल पैलेस होटल के गेट सील किए जाने के बाद यह विवाद काफी सुर्खियों में आया था। उस समय शिखर अग्रवाल जेडीए आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। हाईकोर्ट के पूर्व के एक आदेश के अनुसार, राज्य सरकार और जेडीए की ओर से दायर अपीलों में प्रतिवादियों के नाम के साथ महाराजा, प्रिंसेस और राजमाता जैसी उपाधियां बरकरार रखी गई हैं।

यह विवाद राजमहल पैलेस और ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह सहित अन्य से जुड़ी करीब 120 बीघा और 14 बिस्वा जमीन से संबंधित है।

This newspaper/periodical is published by Sheikh Rais Ahmed from 2660, Garnala Ni Pole, Near Halim Ni Khadki, Shahpur, Ahmedabad, Gujarat - 380001 on behalf of Sheikh Rais Ahmed, edited by Ashokkumar Kantilal Jambukiya and printed by Gujarat Garjana Offset at Gujarat Garjana Offset, B/13, Shri Sainath Industrial Estate, Near G D High School, Behind Kubereshwar Mahadev, Saijpur Bogha, Naroda, Ahmedabad, Gujarat - 382345Ð